

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3741
जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
27अग्रहायण, 1946 (शक)

डीपीडीपी अधिनियम के अंतर्गत नियम

3741.डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने और कार्यान्वित करने की वर्तमान स्थिति क्या है और उन्हें अंतिम रूप देने और लागू करने की संभावित समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या डीपीडीपी नियमों का प्रारूप तैयार करने में हितधारकों के साथ परामर्श किया गया था और यदि हां, तो प्राप्त किए गए प्रमुख फीडबैक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा इसके प्रावधानों से प्रभावित होने वाले अन्य विधानों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) को 11 अगस्त 2023 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। डीपीडीपी अधिनियम के प्रारूपण में उपयोग किए गए कुछ सिद्धांतों, जैसे सरल भाषा का उपयोग करना, अनावश्यक क्राॅस रेसिंग से बचना, प्रासंगिक परिभाषा उपलब्ध कराना और उदाहरण प्रदान करना आदि का डीपीडीपी नियमों के प्रारूपण में भी पालन किया गया है।

डीपीडीपी अधिनियम के प्रारूपण के दौरान किए गए विस्तृत अभ्यास के बाद, नियमों के प्रारूपण के लिए भी इसी तरह का विस्तृत अभ्यास किया गया है।

नियमों का प्रारूपण करते समय उद्योग निकायों, सिविल सोसाइटियों, सरकारी संगठनों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा और परामर्श किए गए हैं। नियमों का प्रारूपण अंतिम चरण में है। डीपीडीपी नियमों पर आगे का

परामर्श मौजूदा नियमों के प्रकाशन के बाद किया जाएगा। डीपीडीपी अधिनियम के ये प्रावधान कुछ समय के लिए लागू किसी भी अन्य कानून के अतिरिक्त हैं और इनसे उस कानून का उल्लंघन नहीं होता है।
